industry projects. In order to improve availability of credits of Khadi & Village Industry (KVI) sector, the Government have also given gurantee in favour of the KVIC so that they could avail of loans upto Rs. 1000 crores from a consortium of banks for further lending to viable KVI projects. This has been done in accordance with the announcement made by the Finance Minister in his budget speech for the year 1995-96 as part of the measures for improving availability of bank credit for the KVI sector.

Exodus of Senior Doctors from AIIMS

504. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the exodus of senior doctors from the AIIMS continuous unabated;

(b) if so, what is the number of senior doctors who left the AIIMS during the last six months;

(c) whether a Committee of senior doctors was set up to identify the causes for the exodus of AIIMS doctors; and

(d) if so, what are the findings of the Committee and what action has been taken by Government thereon?

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI A.R. ANTULAY): (a) to (d) Some doctors at middle level have left AIIMS for alternative jobs. A Committee of Senior doctors has been formed by the Director and its report will be placed before the Governing Body of the Institute.

छत्तीसगढ़ में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना

505. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने के प्रस्ताव के संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार को इस संबंध में विभिन्न सामाजिक संगठनों और वकीलों से अब तक कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) क्या छत्तीसगढ़ में न्यायपीठ के संबंध में रायपुर के दावे पर विचार किया जा रहा है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (घ) विभिन्न स्थानों पर, जिनके अन्तर्गत मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रायपुर भी है, उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने के लिए विभिन्न संगठनों और व्यष्टिकों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। अभ्यावेदनों की संख्या बताना संभव नहीं है। इस विषय को 1983 में जसवंत सिंह आयोग को निर्दिष्ट किया गया था। आयोग ने अप्रैल, 1985 में सरकार को प्रस्तुत की गई अपनी रिपोर्ट में रायपुर में उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना करने की सिफारिश की है।

जसवंत सिंह आयोग की विनिर्दिष्ट सिफारिशों को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अक्तूबर, 1986 में मध्य प्रदेश सरकार को विचार और टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 (2) के निबंधनों के अनुसार राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अतः यह विषय केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

Manufacture of Main Battle Tank

506. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the status of development and manufacture of the Main Battle Tank; and

(b) whether any shortcomings are still to be removed and improvements are considered necessary?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (DEPARTMENT OF DEFENCE AND